RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 14 JULY TO 20 JULY 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 47 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

पिछले वित्त वर्ष में पकड़ी गई 35 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी Page 3

निजी-स्कूल और उनकी लगातार बढ़ती फीस Page 5

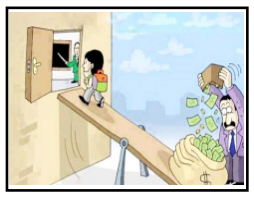

ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, मिल सकता है ज्यादा ब्याज Page 7

editoria!

टैक्स विवाद खत्म हो

ब्रिटेन की पेट्रोलियम कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी के साथ एक टैक्स विवाद में भारत सरकार को झटका लगा है। इस मामले में फ्रांस की एक अदालत ने पैरिस में भारत सरकार की संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। कुछ ही महीने पहले केयर्न ने इसी तरह से अमेरिका में एयर इंडिया की संपत्ति पर दावा किया था। वह इन कदमों से पिछले साल एक अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेश के मुताबिक भारत सरकार पर बकाए के भुगतान का दबाव बना रही है। असल में, 2007 में वोडाफोन ने भारतीय टेलिकॉम कंपनी हचिसन-एस्सार में हचिसन की 67 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी। कुछ साल बाद इस सौदे पर ब्रिटिश कंपनी से 20 हजार करोड़ का टैक्स मांगा गया। वोडाफोन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और केस जीत गई। इसके बाद सरकार ने 2012 में पिछली तारीख से टैक्स लगाने का कानून बना दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेमानी हो गया। वोडाफोन ने तब भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन अदालत में चुनौती दी। सितंबर, 2020 के आखिर में वोडाफोन वहां भी केस जीत गई। केयर्न एनर्जी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। वह 2007 में अपनी भारतीय इकाई केयर्न इंडिया का आईपीओ लेकर आई। एक साल पहले उसने केयर्न इंडिया के साथ कई अन्य भारतीय इकाइयों को मिलाया था। इसके सात साल बाद टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कई इकाइयों को मिलाने से आपको कैपिटल गेन हुआ। इसलिए उस पर टैक्स चुकाना होगा। इसमें भी पिछली तारीख से टैक्स वसूलने वाले कानून का इस्तेमाल किया गया। केयर्न ने भी इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। इस बीच टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 हजार करोड़ से अधिक बकाये की एवज में केयर्न इंडिया के 10 फीसदी शेयर बेच दिए। यह काम एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुआ। पिछले साल के अंत में नीदरलैंड्स में हेग के आर्बिट्रेशन कोर्ट ने भारत सरकार से ब्याज सहित यह रकम केयर्न को चुकाने का निर्देश दिया। केयर्न और वोडाफोन, दोनों ही मामलों में आर्बिट्रेशन कोर्ट ने कहा कि द्विपक्षीय समझौतों को तोड़कर भारत का कंपनियों पर टैक्स लगाना गलत है। इन दोनों ही मामलों में सरकार ने अपील की है। केयर्न एनर्जी के मामले में हालिया फैसले का एक असर यह हो सकता है कि जो भी देश न्यूयॉर्क आर्बिट्रेशन कन्वेंशन के सदस्य हैं, वे कंपनी को अपने हितों की रक्षा करने की इजाजत देंगे। इससे भारत सरकार की और फजीहत होगी। दूसरे देशों में उसकी और संपत्तियों के फ्रीज होने की सूरत बन सकती है। दूसरी बात यह है कि ऐसे मामलों से विदेशी निवेशकों के बीच देश की छवि खराब होती है। यूं भी एनडीए 2014 में टैक्स टेररिज्म खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। इसलिए अच्छा यही होगा कि सरकार को आपसी बातचीत से इस मसले को सुलझा ले। इसका संकेत गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने दिया भी। उसने कहा कि वह देश के कानून के मुताबिक केयर्न एनर्जी के साथ विवाद सुलझाने को तैयार है।

डेढ़ साल बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बहाल, 17 से बढ़कर 28 फीसदी हुआ डीए

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए आज का दिन बेहद खास है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते यानी डीए पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 17 फीसदी की जगह 28 फीसदी डीए मिलेगा। सरकार ने कोरोना की वजह से डेढ़ साल से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक रखा था। अब यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2021 से लागू होगी। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का एरियर देने पर फैसला नहीं लिया गया है।

17 से 28 फीसदी हुआ डीए

जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही (जून 2020) में इसमें तीन फीसदी का इजाफा हुआ। जनवरी 2021 में यह चार फीसदी और बढ़ा था। इस तरह डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी होने से कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि सरकार ने पिछले साल जनवरी से ही इसमें रोक लगाई हुई थी। अब डेढ़ साल बाद तीनों किस्तों पर लगी रोक हटा दी गई है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा था। वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके लिए सरकार लगभग 34,401 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

क्या है महंगाई भत्ता?

मालूम हो कि महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित फीसदी होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता है।

इस तरह होती है डीए की गणना

महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है।

Crude oil की मांग बढ़ी पर OPEC+ देश नहीं बढ़ा रहे उत्पादन

नई दिल्ली। एजेंसी

वैक्सीनेशन में तेजी के चलते आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने से पिछले महीने तेल की मांग में वृद्धि हुई, लेकिन ओपेक + देशों द्वारा आवश्यकता से कम उत्पादन करने से कीमतों का अस्थिर रहना तय है, जब तक कि उत्पादन बढ़ाने को लेकर कोई समझौता ना हो जाए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मंगलवार को यह बात कही है। इस महीने की शुरुआत में ओपेक + देशों की एक बैठक हुई थी, लेकिन इसमें गतिरोध देखा गया और उत्पादन में कटौती को धीरे-धीरे कम करने की योजना पर कोई फैसला नहीं हो पाया। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के समय तेल की मांग में भारी कमी के कारण ओपेक + देशों ने उत्पादन में कटौती का फैसला लिया था। हालांकि, अब तेल की मांग फिर से बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एसेंजी का अनुमान है कि इसमें पिछले महीने 3.2 मिलियन बैरल प्रति दिन (mbd) की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले साल मांग में आई कुल गिरावट के एक तिहाई से अधिक है। आईईए का अनुमान है कि जुलाई से तीन महीने में तेल डिमांड 3.3 mbd और बढ़ सकती है। यह साल 2019 में समान अवधि के दौरान दर्ज हुई सीजनल वृद्धि के दोगुने से अधिक है। आईईए का कहना है कि यह कोविड प्रतिबंधों में राहत और वैक्सीनेशन में तेजी का परिणाम है। मांग बढ़ने पर ओपेक + को धीरे-धीरे उत्पादन में वृद्धि करनी थी, लेकिन बैठक में आए गतिरोध का मतलब है कि उत्पादन मौजूदा स्तर से तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक कि कोई समझौता नहीं हो जाता। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी ताजा मासिक रिपोर्ट में कहा, 'तेल की कीमतों ने पिछले हफ्ते ओपेक+ गतिरोध पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो आपूर्ति घाटा गहराने की संभावना है।'

कीमतों का अस्थिर रहना तय

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे टूटा

मुंबई। एजेंसी

अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी के चलते निवेशकों की धारणा प्रभावित होने से रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की गिरावट के साथ 74.61 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 74.57 पर खुला और फिर कमजोरी के साथ 74.61 पर आ गया, जो पिछले बंद के मुकाबले 12 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.49 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 92.72 पर आ गया।वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.31 प्रतिशत गिरकर 76.25 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

सोना खरीदने का सुनहरा मौका! 8300 रुपये तक गिर गए दाम, चांदी भी सस्ती

नई दिल्ली। एजेंसी

मंगलवार को MCX पर सोने का अगस्त वायदा इंट्रा डे में 48,000 रुपये के ऊपर भी गया। लेकिन ज्यादा देर तक टिका नहीं रह सका। हालांकि मंगलवार को ट्रेडिंग एक बेहद छोटे से दायरे में होती रही। अंत में सोना 100 रुपये की मामूली बढ़त पर बंद हुआ। सोना 60-70 रुपये की हल्की मजबूती के साथ खुला है, रेट 47950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर कर रहा है।

सोना उच्चतम स्तर से करीब 8300 रुपये सस्ता

पिछले साल कोरोना संकट की वजह से लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया था, अगस्त 2020 में MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 56191 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सोना अगस्त वायदा MCX पर 47900 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर है, यानी अब भी करीब 8300 रुपये सस्ता मिल रहा है। चांदी का सितंबर वायदा मंगलवार को 300 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि वायदा रेट अब भी 69,000 रुपये के ऊपर ही हैं। चांदी वायदा में फ्लैट शुरुआत हुई है। चांदी वायदा इस समय 69140 रुपये प्रति किलो के लेवल पर कारोबार कर रहा है। चांदी वायदा इस पूरे हफ्ते तक 69,000 रुपये के ऊपर ही बंद हुआ है।

तेल फिसला, चीनी कच्चे तेल के आयात में गिरावट ने ईंधन की मांग को लेकर चिंता जताई

एजेंसी

एशिया में बुधवार की सुबह तेल नीचे था, डेटा दिखाने के बाद कि चीन का कच्चा आयात 2021 की पहली छमाही में गिरा, जिससे ईंधन की मांग की चिंता बढ़ गई। हालाँकि, काला तरल अभी भी एक सप्ताह के उच्च स्तर के पास बना हुआ है क्योंकि आपूर्ति की चिंताएँ COVID-19 से आर्थिक सुधार के साथ-साथ बनी हुई हैं। Brent oil futures पिछले सत्र के दौरान 1.8% उछलने के बाद दोपहर 12:43 बजे ET (4:43 AM GMT) तक 0.34% बढ़कर 76.23 डॉलर हो गया। WTI फ्यूचर्स मंगलवार को 1.6% की बढ़त के बाद 0.45% गिरकर 74.91 डॉलर पर बंद हुए।

दुनिया के शीर्ष तेल आयातक चीन में कच्चे तेल का आयात साल-दर-साल जनवरी से जून 2021 तक 3% गिरा। आयात कोटा की कमी, रिफाइनरी के रखरखाव और बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण खरीद कम हुई जिसके परिणामस्वरूप 2013 के बाद इस तरह का पहला संकुचन हुआ।

'कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आयात में कमी आई है, जिससे रिफाइनरी का लाभ मार्जिन कम हो गया है ... यदि ओपेक+ जल्द ही आपूर्ति बढ़ाने के लिए सहमत नहीं होता है, तो उच्च तेल की कीमतें भी अधिक लागत-संवेदनशील उभरते बाजारों में मांग विनाश का कारण बन सकती हैं, विशेष रूप से भारत, 'यूरेशिया समूह के विश्लेषकों ने एक नोट में कहा। नोट में पेट्रोलियम निर्यातक देशों और सहयोगियों (ओपेक+) के संगठन के भीतर आपूर्ति नीति पर चल रही असहमति का उल्लेख किया गया है, जिसने अगस्त के लिए उत्पादन वृद्धि को छोड़ दिया है, जो अब तीन सप्ताह से भी कम समय में अधर में है। महीने की शुरुआत में हुई बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म होने के बाद भी कार्टेल की बैठक होनी बाकी है। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि 2021 की तीसरी तिमाही में भंडारण से वैश्विक निकासी कम से कम एक दशक में सबसे अधिक होने का अनुमान है, यू.एस. यूरोप और जापान में जून की शुरुआत में स्टॉक ड्रॉ के कारण। मंगलवार को जारी अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान के अमेरिकी कच्चे तेल की आपूर्ति के आंकड़ों ने 9 जुलाई को समाप्त सप्ताह के लिए 4.079 मिलियन बैरल का ड्रॉ दिखाया। पूर्वानुमानों में 4.333 मिलियन-बैरल ड्रॉ और पिछले सप्ताह के दौरान दर्ज किए गए 7.983-मिलियन-बैरल ड्रॉ दोनों से छोटा था। निवेशक अब अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन से कच्चे तेल की आपूर्ति के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जो बाद में दिन में आने वाला है।

तेल की सस्ती कीमतों के लिए पेट्रोलियम मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात से संपर्क किया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत में ईंधन की कीमतों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बीच देश के नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस उद्देश्य से उन्होंने तेल उत्पादक देशों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। पुरी ने पिछले हफ्ते कतर के ऊर्जा मंत्री को फोन किया था और उन्होंने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अपने समकक्ष सुलतान अहमद अल जाबेर को फोन किया।

पुरी ने ट्विटर पर लिखा, 'हमने उपभोक्ताओं के लिए और सस्ती कीमतों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ऊर्जा क्षेत्र के दूसरे आपूर्तिकर्ताओं में स्थिरता, निश्चिंतता एवं व्यावहारिकता की भावना लाने के लिए यूएई तथा अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर काम करने की अपनी इच्छा जतायी।' मांग में सुधार के साथ तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में फिर से तेजी आने की वजह से भारत में पेट्रोल और ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयी हैं। मई में अंतरराष्ट्रीय कीमतें गिर गयी थीं। देश के डेढ़ दर्जन से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल ने 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि राजस्थान और ओडिशा में डीजल 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक के दाम पर बिक रहा है। पुरी ने कहा, 'यूएई के उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री तथा एडनॉक ग्रुप के प्रबंध निदेशक एवं ग्रुप सीईओ डॉ. सुलतान अहमद अल जाबेर के साथ फोन पर बातचीत की।'' हमने भारत और यूएई की गतिशील द्विपक्षीय रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी में नयी ऊर्जा भरने के तरीकों पर चर्चा की।' अपनी ऊर्जा जरूरतों के 85 प्रतिशत हिस्से का आयात करने वाला भारत पिछले काफी समय से तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और उसके सहयोगी यानी ओपेकप्लस देशों से उत्पादन में की जा रही उनकी कटौती को खत्म करने तथा तेल की कीमतों को वाजिब स्तरों पर लाने में मदद करने की अपील करता रहा है।

कच्चे तेल में फिर भारी तेजी पर यहां कीमतों में दूसरे दिन भी फेरबदल नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल की चाल सबको परेशान कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड फिर प्रति बैरल एक डॉलर से ज्यादा की छलांग लगा गया। लेकिन घरेलू बाजार में इन दिनों पेट्रोल डीजल के दाम में फेरबदल नहीं हो रहे हैं। पिछले दो दिनों से दोनों ईंधन के दाम स्थिर हैं। उससे एक दिन पहले पेट्रोल की कीमत तो बढ़ी थी, लेकिन डीजल की कीमत घटी थी। दिल्ली के बाजार में बुधवार को इंडियन ऑयल (IOC) के पंप पर पेट्रोल 101.19 रुपये प्रति लीटर पर जबकि डीजल भी 89.72 रुपये प्रति लीटर पर यथावत रहा।

40 दिनों में ही 10.87 रुपये महंगा हो चुका है पेट्रोल

ऐसा देखा गया है कि अपने यहां जब कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने की वजह से बीते मार्च और अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसलिए, उस दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन, बीते चार मई से इसकी कीमतें खूब बढ़ी। कभी लगातार तो कभी ठहर कर, 40 दिनों में ही पेट्रोल 10.87 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है।

करीब तीन महीने के बाद एक दिन सस्ता हुआ है डीजल

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने बीते 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने 27 फरवरी 2021 को डीजल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। फिर दो महीने से भी ज्यादा समय तक इसके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि, बीच में 15 अप्रैल को डीजल के दाम में 14 पैसे की मामूली कटौती हुई थी। चुनाव बीतने के बाद बीते 4 मई से इसमें रूक-रूक कर बढ़ोतरी होना शुरू हुआ। आमतौर पर देखा जाता है कि जिस दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, उसी दिन डीजल के भी दाम बढ़ते है। लेकिन शुक्रवार, दो जुलाई 2021 को सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़े थे। डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। सोमवार, 5 जुलाई को भी सिर्फ पेट्रोल का दाम बढ़ा जबकि डीजल स्थिर रहा। सोमवार, 12 जुलाई को तो पेट्रोल की मत बढ़ने के बावजूद डीजल के दाम में कमी हुई।

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने तेल फील्ड मंजूरी प्रक्रियाओं को सुगम बनाया, कागजी काम कम किये

नयी दिल्ली। एजेंसी

तेल नियामक डीजीएच ने तेल फील्डों के लिये मंजूरी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिये कदम उठाया है। इसके तहत सांविधिक मंजूरी की जरूरतों को केवल अनुबंधों के विस्तार, हिस्सेदारी की बिक्री और सालाना खाता तक सीमिति रखते हुए बाकी कामों के लिए स्व-प्रमाणन की व्यवस्था के साथ कंपनियों के लिये देश में तेल और गैस खोज एवं उत्पादन को आसान बनाया गया है। तेल एवं गैस खोज और उत्पादन पर नजर रखने वाली सरकार की तकनीकी इकाई हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने कहा कि नई खोज लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) के तहत नौ दौर की बोलियों के अंतर्गत आबंटित तेल एवं गैस ब्लॉक तथा नेल्प से पहले के ब्लॉक के लिये पक्रियाओं को सरल और मानकीकृत बनाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) नामित आधार पर आबंटित ब्लॉक या क्षेत्रों से देश के तेल एवं गैस का दो तिहाई उत्पादन कर रही है। शेष उत्पादन

नेल्प ब्लॉक और उससे पहले के ब्लॉक से किये जा रहे हैं। नेल्प पूर्व ब्लॉक में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में पन्ना/मुक्ता और ताप्ती तेल एवं गैस फील्ड तथा केजी बेसिन में रावा फील्ड शामिल हैं। डीजीएच ने 12 जुलाई के अपने आदेश में कहा, ''सरकार के लिये खोज और उत्पादन क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाने के साथ कारोबार सुगमता पर विशेष जोर है। प्रक्रियाओं को सरल बनाये जाने और मानकीकरण से व्यवस्था पारदर्शी और दक्ष बनेगी।'' हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने नेल्प और नेल्प से पहले के ब्लॉक को लेकर उत्पादन साझोदारी अनुबंधों (पीएससी) के तहत विभिन्न मंजूरी और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रियाओं की समीक्षा की है। नेल्प या नेल्प से पहले के दौर के तहत दिए गए ब्लॉक में तेल और गैस की खोज करने वाली एक कंपनियों को 37 प्रक्रियाओं के पालन करने की आवश्यकता थी। इन्हें अब घटाकर 18 कर दिया गया है। इनमें से आधे मामलों में स्वतः प्रमाणपत्र की अनुमति दी गयी है। इसमें खोज को वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक होने की घोषणा के साथ-साथ तिमाही रिपोर्ट, बीमा और बैंक गारंटी जमा करने की जरूरतें शामिल हैं।

डीजीएच के अनुसार इन प्रक्रियाओं के लिये अब कोई मंजूरी की जरूरत नहीं है।

अब केवल अनुबंध या खोज चरण के विस्तार अथवा ठेकेदार के ब्लॉक से बहार निकलने या बिक्री के लिये ही ब्लॉक निगरानी समिति, डीजीएच या पेट्रोलियम मंत्रालय की पहले से मंजूरी की जरूरत होगी। इसके अलावा, वर्ष के अंत में लेखा विवरण, योजना से बाहर होने और अधूरी परियोजना की लागत के संदर्भ में भी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी । डीजीएच ने कहा, ''अब अनुबंधन अनुपालन से जुड़ी 37 प्रक्रियाओं को समाहित कर 18 प्रक्रियाओं में शामिल किया गया है।'' इसके जरिये कुल मिलाकर प्रक्रियाओं को दुरूस्त किया गया है। इसके अलावा अब सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की सुविधा होगी।

मंत्रिमंडल ने भारतीय जहाजरानी कंपनियों के लिए 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में सरकारी माल के आयात के लिए भारतीय जहाजरानी कंपनियों को पांच वर्षों के दौरान 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की योजना को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जहाजों के पंजीयन की तरह 72 घंटों के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा और इससे भारत में जहाजों का पंजीकरण आसान और आकर्षक हो जाएगा।

बयान में आगे कहा गया, ''इसके अलावा ताजा पहल का मकसद किसी भी ध्वजवाहक पोत को भारतीय चालक दल के साथ चालक दल को बदलने के लिए 30 दिन का समय देना है।'' भारतीय ध्वजवाहक जहाजों को होने वाले लागत नुकसान को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आम बजट 2021-22 के भाषण में पांच वर्षों में 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता देने की घोषणा की थी। बयान में कहा गया है कि जहाजों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़कर उन पर कार्मिक आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

मप्र-छग में मोबाइल ग्राहक 8 करोड़ के करीब, कोरोना काल में भी जियो का दबदबा कायम

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सर्किल में मोबाइल ग्राहक 8 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। ट्राई के अप्रैल 2021 के जारी आंकड़ों में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने अप्रैल के महीने में 5.37 लाख ग्राहक जोड़े हैं। वहीं एयरटेल ने 45.3 हजार ग्राहक जोड़े। दूसरी तरफ वोडाफोन के 1.49 लाख और बीएसएनएल के 1 लाख ग्राहक घट गए।

टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सर्किल के लिए टेलीकॉम ग्राहकों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अप्रैल 2021 के महीने में मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 7.82 करोड़ हो गई। जियो सर्किल में पहले स्थान पर कायम है। ट्राई की जारी रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में रिलायंस जियो ने अप्रैल 2021 में 5.37 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। सर्किल में जियो के 3.5 करोड़ ग्राहक हैं। जियो कोरोना काल के दौरान अपनी अनवरत सेवा को जारी रखकर मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में ग्राहक जोड़ने में कामयाब रही।

रिपोर्ट के मुताबिक भारती एयरटेल के ग्राहक 45.3 हजार बढ़कर 1.54 करोड़ हो गए हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 1.49 लाख घटकर 2.14 करोड़ हो गई है। सरकारी कंपनी बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या 1 लाख घटकर 62.1 लाख हो गई। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में कुल मोबाइल ग्राहक 3.32 लाख बढ़कर 7.82 करोड़ हो गए। अप्रैल 2021 के महीने में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान जियो के फाइबर ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 9369 बढ़कर 1.88 लाख हो गई। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में कुल 7.22 लाख वायरलाइन सब्सक्राइबर हैं। अप्रैल 2021 में पूरे देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 118.3 करोड़ रही। पूरे देश में रिलायंस जियो के 42.7 करोड़ ग्राहक, एयरटेल के 35.2 करोड़, वोडाफोन आइडिया के 28.1 करोड़ और बीएसएनल के 11.7 करोड़ ग्राहक हैं।

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में मोबाइल ग्राहक- अप्रैल 2021

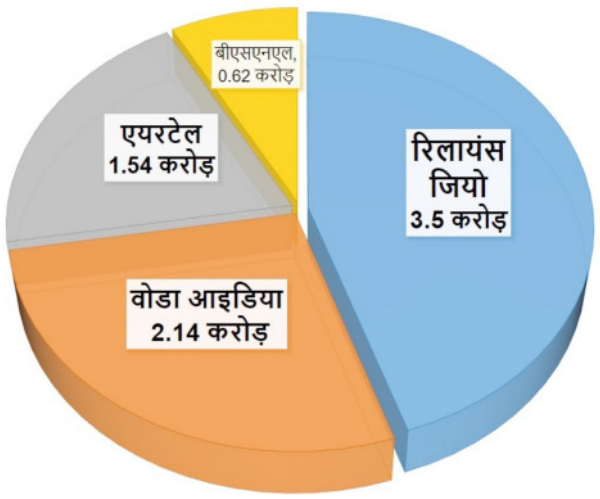

परिधान तथा मेड-अप के लिए आरओएससीटीएल लाभों को जारी रखना बड़ी सहायता

एक क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होगा: फियो अध्यक्ष डॉ. ए शक्तिवेल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल को 31 मार्च, 2024 तक परिधान तथा मेड अप के लिए आरओएससीटीएल लाभों को उन्हीं दरों पर जो मार्च 2019 में अधिसूचित थे, जारी रखने के लिए उन्हें स्वागत और धन्यवाद करते हुए फियो अध्यक्ष डॉ. ए शक्तिवेल ने कहा कि यह परिधान तथा मेड अप सेक्टरों के लिए एक बड़ी सहायता है और यह उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में

बेशुमार सहायता करेगी।

लगभग तीन वर्षों के लिए स्कीम का विस्तार स्थिरता और संभाव्यता प्रदान करता है जो दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए बहुत अच्छा शकुन है और इससे सेगमेंट में अतिरिक्त निवेश सुनिश्चित होगा तथा सेक्टर में नए रोजगारों का सृजन होगा। फियो प्रमुख ने कहा कि कई पड़ोसी देश हमारे प्रतिस्पर्धी बन कर उभरे हैं जिन्हें एलडीसी दर्जे के कारण या प्रभावी मुक्त व्यापार समझौतों की वजह से प्रशुल्क (टैरिफ) का लाभ हासिल है। आरओएससीटीएल का विस्तार और अमेरिका, ब्रिटेन, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते भारतीय परिधान और मेड अप सेक्टरों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन (गेम चेंजर) साबित होंगे और इस सेक्टर को वैश्विक व्यापार में इसका उचित स्थान दिलाने में सहायता करेंगे। फियो अध्यक्ष ने सरकार से आग्रह किया कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी जल्द ही आरओडीटीईपी दरों की घोषणा कर दी जाए जिससे कि निर्यातक 1 जनवरी, 2021 से इसका लाभ उठा सके और उनकी तरलता में बढोतरी हो।

केंद्र सरकार ने दी राहत

ऑक्सीमीटर सहित पांच चिकित्सा उपकरण सस्ते होंगे

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑक्सीमीटर व डिजिटल थर्मामीटर सहित पांच चिकित्सा उपकरणों पर अधिकतम ट्रेड मार्जिन 70 फीसदी तय कर दिया है। यह कदम महामारी को देखते हुए कीमतें घटाने के लिए उठाया गया है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने बताया कि ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर पर ट्रेड मार्जिन की अधिकतम सीमा 70 फीसदी रहेगी। एनपीपीए ने ट्वीट कर बताया कि अभी इन उपकरणों पर 3-709 फीसदी तक मार्जिन होता है। कोविड-19 संकट को देखते हुए इन उत्पादों की कीमतें घटाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नई दरें 20 जुलाई, 2021 से लागू हो जाएंगी। ट्रेड मार्जिन किसी उत्पाद की वास्तविक खरीद और वितरकों द्वारा उसके अंतिम बिक्री मूल्य के बीच का अंतर होता है। यह सीमा 70 फीसदी तय होने से वितरक अब 100 रुपये के उत्पाद को अधिकतम 170 रुपये तक ही बेच सकेंगे।

पिछले वित्त वर्ष में पकड़ी गई 35 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी

नई दिल्ली। एजेंसी

कर चोरी के खिलाफ एक साल लंबे अभियान में 35 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की जीएसटी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया है। सीबआईसी के मुताबिक, इनमें से ज्यादातर धोखाधड़ी वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत दिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्रावधान का दुरुपयोग कर अंजाम दी गई।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मंगलवार को बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सीजीएसटी के सभी जोन और जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की टीमों ने फर्जी आईटीसी के जरिये 35 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कर चोरी के करीब 8000 मामले दर्ज किए और इनमें 426 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों में 14 चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकालत जैसे पेशेवर भी शामिल हैं, जो इस कर चोरी को करने में मदद कर रहे थे।

सीबीआईसी के मुताबिक, आईटीसी के जरिये कर चोरी करने वालों को तलाशने के लिए जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत से ही निगरानी की जा रही है, लेकिन ऐसे मामलों की बड़ी संख्या होने का अनुमान मिलने पर पिछले साल 9 नवंबर से एक विशेष राष्ट्रीय स्तर का अभियान शुरू किया गया था, जो अब भी चल रहा है। इस अभियान में फर्जी आईटीसी दावों की छानबीन कर उन्हें सामने लाया जा रहा है। सीबीआईसी के मुताबिक, इस वित्त वर्ष में भी अब तक 500 से ज्यादा जीएसटी फर्जीवाड़े के मामले पकड़े जा चुके हैं। करीब 1200 कंपनियों से जुड़े इन मामलों में 24 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यवस्था

बता दें कि जीएसटी व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी प्रावधान के तहत कंपनियां अपने उत्पादन पर वसूला गया कर जमा कराते समय उत्पादन के लिए खरीदे गए कच्चे माल पर चुकाए कर को घटा सकती हैं। कंपनियों पर कर का बोझ घटाने के लिए रखी गई इस व्यवस्था का कुछ लोग कच्चे माल के झूठे इनवॉयस बनाकर आईटीसी दावा करने के जरिये कर चोरी करने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं।

News यू केन USE

कमजोर हाजिर मांग से कच्चातेल वायदा कीमतों में गिरावट

नयी दिल्ली। एजेंसी

कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से वायदा कारोबार में बुधवार को कच्चा तेल की कीमत 25 रुपये की गिरावट के साथ 5,584 रुपये प्रति बैरल रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चातेल के जुलाई डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 25 रुपये अथवा 0.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,584 रुपये प्रति बैरल रह गई जिसमें 5,230 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कच्चातेल कीमतों में गिरावट आने का मुख्य कारण कमजोर हाजिर मांग के बीच व्यपारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करना था। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में वेस्ट टैक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का दाम 0.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ 74.79 डालर प्रति बैरल रह गया। वैश्विक मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड का दाम 0.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76.11 डालर प्रति बैरल रह गया।

कोविड-19 की दूसरी लहर से एफएमसीजी उद्योग के लिए चुनौतियां बढ़ीः आईटीसी

नयी दिल्ली। एजेंसी

आईटीसी लिमिटेड ने कहा कि भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के चलते एफएमसीजी उद्योग के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं और पहली लहर की तुलना में इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस का प्रकोप अधिक रहने से उद्योग की वृद्धि संभावनाओं पर असर पड़ने की आशंका भी है। आईटीसी की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायरस के प्रकोप के कारण भारत में आर्थिक सुधार को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता अब बचत पर जोर दे सकते हैं, जिसके चलते खपत में वृद्धि प्रभावित होगी। इसके अलावा ग्रामीण मांग भी प्रभावित हो सकती है। कंपनी के निदेशकों ने रिपोर्ट में कहा, ''देश में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की गंभीरता एक महत्वपूर्ण चुनौती है और निकट अवधि में एफएमसीजी उद्योग को सजग रहना होगा।''

बोइंग ने 787 ड्रीमलाइनर के उत्पादन में कटौती की

शिकागो। एजेंसी

बोइंग अपने 787 विमान के उत्पादन में कटौती करेगी। यह निर्णय कुछ वितरित किए जाने के लिए तैयार विमानों में संरचनात्मक दोष का पता लगने के बाद किया गया है। शिकागो स्थित कंपनी ने कहा कि ऐसे में 787, जिसे ड्रीमलाइनर भी कहा जाता है, का उत्पादन घटकर प्रति माह पांच से कम रह जाएगा और इसके चलते इस साल उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले विमानों की संख्या में भी कमी आएगी। कंपनी ने एक बयान में कहा, ''हम यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी समय लेंगे कि आपूर्ति से पहले बोइंग विमान उच्चतम गुणवत्ता मानकों को पूरा करें।'' बोइंग के शेयर कारोबार शुरू होने से पहले ही दो प्रतिशत नीचे आ गए थे। चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में 12 ड्रीमलाइनर ग्राहकों को सौंपे गए एक साल पहले इसी तिमाही में 14 ड्रीमलाइनर की डिलीवरी की गयी थी। अमेरिकी सांसदों ने बोइंग कंपनी और विनियामक संघीय विमान प्राधिकरण से बोइंग 787 और 737 मैक्स श्रेणी के विमानों के उत्पादन में दिक्कतों से जुड़े कागजात मांगे थे।

क्या 4 श्रम संहिताओं के बदल जाएंगे नियम? नए श्रम मंत्री कर रहे रिव्यू

नई दिल्ली। एजेंसी

उद्योग की कुछ चिंताओं को दूर करने के प्रयास में सरकार चार श्रम संहिताओं के तहत प्रस्तावित नियमों पर फिर से विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया है कि नए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रस्तावित नियमों की समीक्षा शुरू कर दी है कि क्या किसी बदलाव की जरूरत है। जल्द ही मंत्री द्वारा उद्योग निकायों और ट्रेड यूनियनों से परामर्श करने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने नए मंत्री को नियमों के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें कोई भी सुधार करना उनका विशेषाधिकार है।

चार संहिताओं में शामिल, वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता का उद्योग के लिए रोजगार की लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सरकार ने भत्तों को वेतन के 50% पर सीमित कर दिया है, जिससे इंप्लॉयर्स द्वारा उच्च ग्रेच्युटी भुगतान की संभावना है।

इंप्लॉयर्स चाहते हैं ग्रेच्युटी पेमेंट में 'ग्रैंडफादरिंग क्लॉज'

इंप्लॉयर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली इंडस्ट्री बॉडीज ने सरकार से ग्रेच्युटी भुगतान के लिए एक 'ग्रैंडफादरिंग क्लॉज' पेश करने की मांग की है क्योंकि कोड्स के तहत 'वेतन' की नई परिभाषा से प्रति कर्मचारी लागत में काफी वृद्धि होगी। उन्होंने नई वेतन परिभाषा के तहत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की भी मांग की है, जिसने वेतन के 50% पर भत्ते को सीमित कर दिया है।

गिग वर्कर्स के लिए जल्द से जल्द सामाजिक सुरक्षा चाहती हैं ट्रेड यूनियन्स

दूसरी ओर, ट्रेड यूनियन चाहती हैं कि सरकार गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा को जल्द से जल्द अधिसूचित करे, भले ही कोड के कार्यान्वयन में अधिक समय लग रहा हो। श्रम मंत्रालय की योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा योगदान किए गए पैसे से दस लाख गिग श्रमिकों को हेल्थ कवर प्रदान करने की है। यूनियनों ने प्रस्तावित 12-घंटे की दैनिक शिफ्ट पर भी चिंता जताई थी और लंबे समय से वैधानिक नेशनल फ्लोर-लेवल न्यूनतम वेतन को जल्द से जल्द लागू करने पर जोर दे रही हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लेबर कोड्स से न ही कर्मचारियों का कल्याण प्रभावित हो और न ही उद्योग पर वित्तीय या अनुपालन बोझ बढ़े।

जल्द ही राज्यों के साथ बैठक

श्रम मंत्रालय ने इस साल मार्च में सभी चार संहिताओं में अपने डोमेन के तहत नियम बनाए थे। नए लेबर कोड्स 1 अप्रैल से लागू होने वाले थे। हालांकि, ऐसा हो नहीं सका क्योंकि कोई भी राज्य अपने डोमेन में नियमों के साथ तैयार नहीं था। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राज्यों की एक बैठक भी बुलाए जाने की संभावना है ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में नियम बनाने में तेजी लाने के लिए कहा जा सके, जिससे संहिताओं को जल्द से जल्द लागू किया जा सके।

बता दें कि केंद्र ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इनमें मजदूरी संहिता; सामाजिक सुरक्षा संहिता; औद्योगिक संबंध संहिता व व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता शामिल हैं। संसद ने 2020 में चार में से तीन श्रम संहिताओं को पारित किया था, जबकि मजदूरी संहिता को 2019 में ही मंजूरी दे दी गई थी।

ईंधन पर लोगों का खर्च बढ़ा तो कोरोना संकट के दौर में इन जरूरी खर्च में लोग कर रहे हैं कटौती

नई दिल्ली। एजेंसी

वाहन ईंधन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार नई ऊंचाई पर पहुंचने के बीच लोगों को गैर-विवेकाधीन खर्च मसलन किराना, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर अपने खर्च घटाना पड़ रहा है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अर्थशास्त्रियों ने यह बात कही है। एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष द्वारा लिखे गए नोट में कहा गया है कि सरकार को ईंधन पर करों में कटौती करनी चाहिए।

डीजल-पेट्रोल में लगी आग

देश के ज्यादातर महानगरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है। डीजल का दाम भी शतक के करीब पहुंच गया है। हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में डीजल 100 रुपये के आंकड़े को पार चुका है। एक अनुमान के अनुसार ईंधन पर प्रति लीटर 40 रुपये केंद्र और राज्यों को कर के रूप में जाते हैं।

स्वास्थ्य पर खर्च घटा

घोष ने कहा कि अब जबकि उपभोक्ताओं को ईंधन पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है, तो वे स्वास्थ्य पर खर्च घटा रहे हैं। ''एसबीआई कार्ड्स पर खर्च के विश्लेषण से पता चलता है कि ईंधन पर खर्च बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए गैर-विवेकाधीन स्वास्थ्य पर खर्च में कटौती हो रही है।' ''

राशन खर्च में भी कटौती

उन्होंने कहा कि अन्य गैर-विवेकाधीन सामान मसलन किराना तथा विभिन्न उपयोगी सेवाओं पर खर्च में कमी आई है। इन उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय कमी देखने को मिल रही है। घोष ने आगाह किया कि ईंधन पर ऊंचे खर्च का मुद्रास्फीति पर असर पड़ रहा है। जून में लगातार दूसरे महीने मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर रही है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि से मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है।

तत्काल कटौती की जरूरत

नोट में कहा गया है कि करों को सुसंगत कर ईंधन कीमतों में तत्काल कटौती की जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर गैर-विवेकाधीन उत्पादों पर उपभोक्ता खर्च नीचे बना रहा है।

महंगाई के आंकड़े अविश्वसनीय

इस बीच, घोष ने कहा कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुमान मई में मुख्य मुद्रास्फीति 6.30 प्रतिशत रही है। उस समय महामारी की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन रहा था। ऐसे में यह 'आंकड़ा असामान्य' नजर आता है।

मई में औद्योगिक उत्पादन 29.3 फीसदी बढ़ा, इन क्षेत्रों में रही अच्छी ग्रोथ

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश का औद्योगिक उत्पादन मई में सालाना आधार पर 29.3 प्रतिशत बढ़ा है। सरकार ने सोमवार इसके आधिकारिक आंकड़े जारी किए। मई में औद्योगिक उत्पादन की अच्छी ग्रोथ में लो बेस इफेक्ट का हाथ रहा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और खनन सहित कुछ क्षेत्रों में अच्छी ग्रोथ दिखी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मई में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के उत्पादन में 34.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मई में खनन क्षेत्र का उत्पादन 23.3 प्रतिशत तथा बिजली का 7.5 प्रतिशत बढ़ा। मई, 2020 में औद्योगिक उत्पादन में 33.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

जून में खुदरा महंगाई दर में मामूली कमी, जानिए कितनी रही

कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले साल मार्च से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित रहा है। उस समय इसमें 18.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी। अप्रैल, 2020 में औद्योगिक उत्पादन 57.3 प्रतिशत घटा था। पिछले साल फरवरी में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत रही थी। हालांकि, मई के आईआईपी के आंकड़े उम्मीद के मुकाबले थोड़ा कम हैं। इसकी वजह इस साल मई में कई राज्यों में लॉकडाउन है। कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए राज्यों ने लॉकडाउन सहित कई तरह की पाबंदियां लगाई, जिसका असर औद्योगिक गतिविधियों पर भी पड़ा।

आयात शुल्क घटने के बाद भी महंगा हुआ पाम तेल, जानिए वजह

उद्योग के आठ बुनियादी क्षेत्रों (एदी एाम्दि) में से छह में मई में पॉजिटिव ग्रोथ दिखी। मई में कोर सेक्टर का उत्पादन 16.8 फीसदी बढ़ा। आईआईपी में कोर सेक्टर की 40 फीसदी हिस्सेदारी है। अप्रैल और मई में कुल फैक्ट्री उत्पादन की ग्रोथ 68.8 फीसदी रही। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के उत्पादन में मई में 34.5 फीसदी ग्रोथ देखने को मिली।

सीरम इंस्टीट्यूट सितंबर में स्पुतनिक वैक्सीन का निर्माण शुरू करेगा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) ने मंगलवार को कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) सितंबर से अपने संयंत्रों में स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेगा। आरडीआईएफ ने एक बयान में कहा, ''एसआईआई के संयंत्रों में स्पुतनिक वैक्सीन के पहले बैच के सितंबर में तैयार होने की उम्मीद है।''

बयान में कहा गया कि भारत में विभिन्न पक्ष हर साल स्पुतनिक-वी वैक्सीन की 30 करोड़ से अधिक खुराक का उत्पादन करना चाहते हैं। आरडीआईएफ ने कहा, ''तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रिया के तहत एसआईआई को गमलेया सेंटर से सेल और वेक्टर नमूने पहले ही मिल चुके हैं। भारतीय दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा इनके आयात की मंजूरी मिलने के साथ कल्टीवेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।''

निजी-स्कूल और उनकी लगातार बढ़ती फीस

राजकुमार जैन
कम्प्यूटर इंजीनियर

शिक्षा, विशेषकर 'स्कूली शिक्षा' निजी हाथों में किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह ही फलेगी फुलेगी, यह सत्य तो शिक्षा का निजीकरण होते समय ही हम सबको भलीभांति विदित था लेकिन जब यह प्रस्ताव अमल में लाया गया था उस समय हमने ही निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अधिक कीमत पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा को शासकीय विद्यालयों में नाम मात्र की फीस पर दी जा रही शिक्षा से बेहतर माना था ।

और अन्य व्यवसायों की तरह, हर उत्पाद, हर सर्विस की तरह समय के साथ इस शिक्षा प्रदान करने की कीमत भी बढ़ेगी यह भी हमें मालूम था तो अब इस बढ़ी हुई फीस या शिक्षा की बढ़ती कीमत पर भोलेपन से आश्चर्यचकित होकर क्यों दिखा रहे हैं हम?

उस समय हम सबने शिक्षा के निजीकरण का विरोध करना था । जो हमने नहीं किया । एक अपराध किया था जिसकी सजा सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही फीस के रूप में अब मिल रही है।

एक बात हम सबको मालूम थी और आज भी है कि अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की तरह एक व्यवसायी के लिए शिक्षा प्रदान करना भी महज लाभ कमाकर प्रोडक्ट/उत्पाद या सेवा/सर्विस बेचने की तरह एक व्यवसायिक गतिविधि मात्र है, ' पैसा लगाओ पैसा बनाओ ' यही तो व्यवसाय होता है, हर व्यवसायी यही करता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, फिर निजी शिक्षण संस्थान को एक व्यवसाय के रूप में चलाने पर ऐतराज क्यों। जैसे शराब, सिगरेट, तम्बाखू, भांग आदि सामाजिक स्वीकृति और सरकारी सुरक्षा के साये में भारी मुनाफे के साथ बेची जा रही है और हमें कई आपत्ती नहीं है, वैसे ही शिक्षा के निजीकरण को भी सामाजिक और सरकारी दोनों ही तरह की स्वीकृति और सुरक्षा भी हमारे द्वारा दी जा चुकी है और अब यह भी भारी मुनाफे का धंधा बन चुका है।

जब हमने, पूरे समाज ने अपने बच्चों को येन केन प्रकरेण इन शिक्षा बेच रहे संस्थानों (दुकानों)

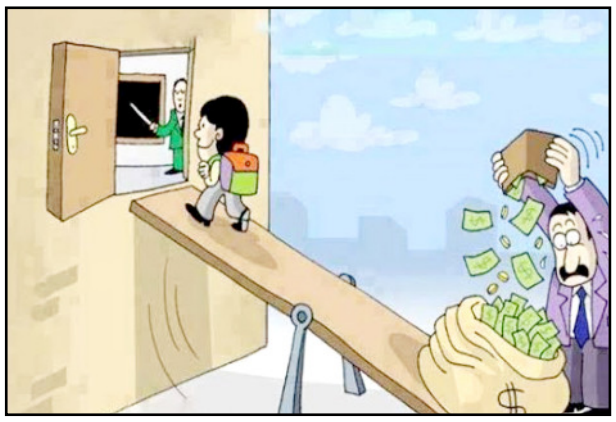

में प्रवेश दिलवाकर इस मुनाफाखोरी को अपनी अपनी सहज और बिना शर्त सहमति प्रदान की हुई है । तो अब इस विषय पर चीख पुकार मचाना व्यर्थ है, बेवजह है, औचित्यहीन है ।

देखा जाय तो इस कार्य से सबका अपना अपना स्वार्थ सिध्द हो रहा है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई है, व्यवसायी मोटा लाभ कमाकर खुश हो गए हैं और पालक इसे स्टेटस सिंबल मानते हैं, बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी मानते हैं और अपनी समझ में अच्छे माने जाने वाले स्कूल में एडमिशन करवा कर निश्चिंत हो गए है।

अब बात करते हैं इस बढ़ती हुई फीस की, तो जितना अच्छा उत्पाद या सेवा होती है उसकी बाजार में उतनी ही अधिक मांग/ डिमांड होती है और जितनी मांग बढ़ती है उतनी ही कीमत भी तो बढ़ती ही है।

अधिक डिमांड कम सप्लाय और बढ़ती कीमत यह तो अर्थशास्त्र का सार्वभौमिक नियम है ।

हमें शराब, सिगरेट पर हो रही मुनाफाखोरी मंजूर है लेकिन शिक्षा हेतु कीमत चुकाने पर ऐतराज क्यों यह मेरी समझ से परे है ।

जब निजी क्षेत्र शिक्षा के लिए खोला गया था उस वक्त हमने इसका विरोध नहीं किया बल्कि खुले ह्रदय से इस निर्णय का स्वागत किया था तो अब यह थोथा विलाप क्यों कर रह हैं हम ?

जो बोया है वो तो काटना ही पड़ता है ।

वैसे भी शासकीय शिक्षण प्रणाली में हम ना तो अपने बच्चों को विद्यार्थी की तरह भेजने को तैयार हैं और ना ही एक शिक्षक की तरह, फिर नैतिक रूप से शासकीय शिक्षा प्रणाली को कोसने का हमें क्या अधिकार है ।

कुछ पाठकों को शिक्षा की तुलना शराब या अन्य नशीले उत्पादों से करना उचित नही लग रहा होगा लेकिन मैंने इस लेख में शराब का उल्लेख सिर्फ ध्यानाकर्षण या चेताने के लिए किया है । वैसे तो शराब और शिक्षा की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि शराब एक तरह का नशा है और सेवन करने वाला नशेड़ी कहलाता है और नशेड़ी नशे की अपनी लत पूरी करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरता है, इसी तरह अपने बच्चे को उस नामचीन और प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन दिलवाने का जो नशा है वह शराब से भी भयावह और घातक रूप में देखा गया है । प्रवेश / एडमिशन फॉर्म के लिए देर रात से लाइन में लग जाना, झूठे दस्तावेजों का सहारा लेना, जुगाड़ लगाना, तिकड़म भिड़ाना, डोनेशन देना, पहचान निकालना, पहुंच या प्रभाव का इस्तेमाल करना, जरूरत पड़ने पर गिड़गिड़ाना, और इसी तरह का कोई भी अन्य हथकंडा जो अपने बच्चे का एडमिशन सुनिश्चित करता ही उसे अपनाने से कतईं कोई गुरेज नहीं करना । यह सब भी एक तरह का नशा ही तो है । जब हम इतने बेकरार है और उतावले भी है निजी शिक्षण संस्थान में अपने बच्चों को भेजने के लिए तो फिर बढ़ती फीस पर सवाल क्यों ? बवाल क्यों ?

इंटरग्लोब फाउंडेशन और साहपीडिया इंदौर की जीवंत विरासत और संस्कृति की खोज करेगा

माई सिटी माई हेरिटेज तीन साल की परियोजना है, जो भारतीय शहरों की संस्कृति और विरासत संभावना की दोबारा छानबीन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। पहले वर्ष में शामिल किये जाने वाले स्थान अहमदाबाद, गोवा, प्रयागराज और शिलांग हैं।

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इंटरग्लोब फाउंडेशन के साथ साझेदारी में साहपीडिया ने 'माई सिटी, माई हेरिटेज' परियोजना की शुरूआत की है जिसके तहत भारतीय शहरों की संस्कृति और विरासत क्षमता की नए सिरे से तलाश की जाएगी। इस परियोजना में भारत में 12 स्थानों की विभिन्न विरासतों और सांस्कृतिक पहलुओं की खोज, प्रलेखन और प्रसार शामिल है, जिसमें सिटी बुकलेट्स का प्रकाशन भी शामिल है। परियोजना के एक हिस्से के रूप में, स्कूली छात्रों और आम दर्शकों के लिए कई हेरिटेज वॉक, म्यूजियम टूर, बैठक और आकर्षक शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है जो 2022 तक चलेगा। पहले वर्ष में शामिल किए गए स्थान अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, गोवा और शिलांग हैं।

पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित इंदौर राज्य के अतीत और वर्तमान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में यह देश के केंद्र में स्थित राज्य में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस शहर में पूर्व में होल्कर राजवंश का शासन था और आज इसे शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। माई सिटी माई हेरिटेज के एक हिस्से के रूप में, परियोजना साहपीडिया ने इंदौर की विरासत और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे निर्मित विरासत, लोगों और समुदायों, स्कृतिक महत्व के संस्थानों और साहित्य और कला के विभिन्न पहलुओं का दस्तावेजीकरण

करने के लिए शहर के लेखकों, शोधकर्ताओं और फोटोग्राफरों के साथ सहयोग किया। इसके अलावा, पुराने को नया करने के साथ-साथ शहर के जीवंत नागरिकों के भीतर भागीदारी, समुदाय और स्वामित्व के नए संबंध बनाने के लिए हाशिए के समुदायों के बच्चों के लिए हेरिटेज वॉक और गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इंदौर में परियोजना का मुख्य आकर्षण बुकलेट 'माई सिटी, माई हेरिटेज, माई इंदौर' है। इसे शहर के बेहतर रहस्यों को नेविगेट करने के लिए एक गाइड के रूप में डिजाइन किया गया है। यह इंदौर की जीवंत विरासत के विभिन्न प्रसिद्ध और अनोखे खजाने का दस्तावेज है।

इस प्रकार, माई सिटी, माई हेरिटेज परियोजना, एक व्यापक उपयोगकर्ता समूह की उम्मीदों को पूरा करता है, जो विकलांग और आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए की पृष्ठभूमि वाले बच्चों, संस्कृति प्रेमियों, विद्वानों, विरासत पेशेवरों और पर्यटकों तक सीमित नहीं है। परियोजना का उद्देश्य सहयोगी अनुसंधान, प्रलेखन और मानचित्रण के माध्यम से युवा स्थानीय विद्वानों की रुचि और क्षमता का निर्माण करना है। इस प्रख्यात परियोजना का माई सिटी, माई हेरिटेज का शुभारंभ समारोह एक सप्ताह तक चलने वाला डिजिटल उत्सव है। इसके लिए विभिन्न आयोजनों और मजबूत सोशल मीडिया अभियानों को न केवल प्रमुख स्थानों पर किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने और सेलिब्रेट करने के लिए, बल्कि सांस्कृतिक प्रणेताओ , व्यापारियों, शिक्षाविदों और नागरिकों के साथ खुली बातचीत के लिए भी तैयार किया गया है। शुभारंभ समारोह में डिजिटल वॉक , प्रदर्शन, क्विज़, प्रतियोगिताएं और इसी तरह की कई गतिविधियाँ शामिल होंगी!

'ज़िंदगी बदल देगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन'

मोटिवेशनल स्पीकर अंजना रितौरिया ने कहा अंजना की किताब हुई है मशहूर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जिंदगी बदलने वाली किताब लिख कर मशहूर हुई अंजना रितौरिया ने बुधवार को अपनी सफलता अपने स्टूडेंट्स और लिसनर्स के साथ सेलिब्रेट की। अपने यूट्यूब चैनल की कामयाबी पर उन्होंने देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैले उनके लिस्नर्स को मोटिवेशनल स्पीच दी और अपनी किताब '40 से 40 करोड़ : लॉक डाउन के 40 दिन' पर भी बात की।

अंजना रितोरिया एक मोटिवेशनल स्पीकर है और उनके लिस्नर्स और स्टूडेंट इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश के अन्य शहरों सहित देश के कई राज्यों और दुनिया के कई देशों में मौजूद है। कुछ दिनों पूर्व शुरू किए गए उनके यूट्यूब चैनल की कामयाबी पर अंजना ने स्टूडेंट के बीच लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रखा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब सभी जगह नकारात्मक बातें हो रही थी, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाकर उन्होंने खुद को सकारात्मक बनाए रखा और यही उनके जीवन में आए बदलाव का कारण भी बना। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के असर के कारण ही उनकी किताब चर्चा में है और बेस्ट सेलर के रूप में लोगों के बीच है।

अपनी मोटिवेशनल स्पीच और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कहते हुए अंजना ने बताया कि आप जिंदगी में जो चाहते हैं, वैसा ही सोचना और कहना शुरू कर दें, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बिल्कुल उस और बढ़ रही है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने खुद अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सकारात्मक प्रभाव होते देखा है। उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह होता है, लेकिन लोगों को बस यह पता नहीं होता कि उसे कहां एप्लीकेबल करना है और अंजना ने अपनी किताब '40 से 40 करोड़ : लॉकडाउन के 40 दिन' में इसी बात को समझाया है।

अंजना की किताब एमेजान पर मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्थ कैटेगरी में बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हुई है। लाकडाउन के 40 दिनों में लिखी गई इस किताब के बारे में अंजना बताती हैं, एक दिन जब उन्होंने यह समाचार पढ़ा कि एक युवा ने कोरोना संक्रमण की जांच के बाद आत्महत्या का प्रयास महज इसलिए किया कि कहीं रिपोर्ट पाजिटिव न आ जाए, तो लगा बेहतर की ख्वाहिश में हमें बेहतर ही सोचना होगा, इसलिए अपने अनुभवों को इस किताब में शामिल किया।

शुरू हो रहा है शिव भक्तों का महीना, जानिए क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार साल का पांचवा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इसे सावन का महीना कहते हैं। सोमवार को भी भगवान शिवका दिन माना जाता है। इस वजह से सावन के सोमवार का खास महत्व होता है। इस बार सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगा। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। इस महीने में कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करती हैं। यहां हम सोमवार की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में बता रहे हैं।

क्या है इस महीने का महत्व

हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस महीने भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही स्मा व्रत करने से तुरंत फल मिलता है और विवाह से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती हैं। खसाकर कुंवारी कन्याएं योगय वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की अराधना करती हैं। सावन के महीने में विधि विधान से पूजा-पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

कब हैं सावन के सोमवार

सावन महीने का पहला सोमवार 26 जुलाई, दूसरा सोमवार 2 अगस्त, तीसरा सोमवार 9 अगस्त और चौथा सोमवार 16 अगस्त को है। जबकि सावन का महीना 25 जुलाई को शुरू होगा और 22 अगस्त को समाप्त होगा। पहली सोमवारी 26 जुलाई और आखिरी सोमवारी 16 अगस्त को होगी। इस बीच कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत शुक्रवार के दिन 6 अगस्त को रखा जाएगा।

क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त

सावन के महीने में चतुर्दशी तिथि 6 अगस्त को शाम 6 बजकर 28 मिनट पर शुरू होगी और 7 अगस्त को शाम 7 बजकर 11 मिनट तक चलेगी। इसके बाद निशिता काल पूजा 7 अगस्त को सुबह 12 बजकर 06 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक चलेगा। 7 अगस्त की सुबह 5 बजकर 46 मिनट से दोपहर 3 बजकर 45 मिनट के बीच शिवरात्रि के व्रत का पारण किया जा सकेगा।

कैसे करें भगवान शिव की पूजा

सावन में चतुर्दशी की तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। अब भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भोलेनाथ को समक्ष धूप, दीपक प्रज्वलित कर शिव शंभू के मंत्रों का उच्चारण करें। अब भगवान शिव को 1001 बेलपत्र अर्पित करें और जल या दूध, दही से रुद्राभिषेक करें। उन्हें धतूरा, भांग, गुड़, पुआ, हलवा, दूध से बनी मिष्ठान चढ़ाएं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।

देवशयनी एकादशी विशेष : कौन से मंत्र और स्तुति से श्रीहरि होंगे प्रसन्न

देवशयनी एकादशी पर विष्णु की यह प्रिय स्तुति मंत्र पढ़ने से वे जीवन को खुशहाल बनाकर आशीष प्रदान करते है। आइए पढ़ें.

विष्णु-स्तुति

शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम्।
लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्व लौकेक नाथम्॥
यं ब्रह्मा वरुणैन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वानि दिव्यै स्तवैवेदेः।
सांग पदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगाः।
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यति यं योगिनो
यस्यातं न विदुः सुरासुरगणा दैवाय तस्मै नमः॥

1. देवशयनी एकादशी संकल्प मंत्र
सत्यस्थः सत्यसंकल्पः सत्यवित् सत्यदस्तथा।
धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्मविवर्जितः॥
कर्मकर्ता च कर्मैव क्रिया कार्यं तथैव च।
श्रीपतिर्नृपतिः श्रीमान् सर्वस्यपतिरूर्जितः॥

2. देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र -
सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदम।
विबुद्धे त्वयि बुध्येत जगत सर्वं चराचरम।

3. देवशयनी एकादशी विष्णु क्षमा मंत्र
भक्तस्तुतो भक्तपरः कीर्तिदः कीर्तिवर्धनः।
कीर्तिदीप्तिः क्षमाकान्तिर्भक्तश्चैव दया परा॥

देवशयनी एकादशी विशेष

क्या सच में देव सोते हैं...?

शास्त्रानुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 'विष्णुशयन' या 'देवशयनी' एकादशी कहते हैं। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 20 जुलाई 2021 को है। 'देवशयनी' एकादशी अर्थात् भगवान् के शयन का प्रारंभ। देवशयन के साथ ही 'चातुर्मास' भी प्रारंभ हो जाता है। देवशयन के साथ ही विवाह, गृहारंभ, गृहप्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक प्रसंगों पर विराम लग जाता है।

हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि हमने देश-काल-परिस्थितिगत व्यवस्थाओं को भी धर्म व ईश्वर से जोड़ दिया। धर्म एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से प्रवाहमान रखने हेतु यह आवश्यक था कि इसके नियमों का पालन किया जाए।

किसी भी नियम को समाज केवल दो कारणों से मानता है पहला कारण है- 'लोभ' और दूसरा कारण है- 'भय', इसके अतिरिक्त एक तीसरा व सर्वश्रेष्ठ कारण भी है वह है- 'प्रेम' किंतु उस आधार को महत्व देने वाले विरले ही होते हैं। यदि हम वर्तमान समाज के ईश्वर को 'लोभ' व 'भय' का संयुक्त रूप कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

क्या देव भी सोते हैं...!

हिंदू धर्म के देवशयन उत्सव के पीछे आध्यात्मिक कारणों से अधिक देश-काल-परिस्थितगत कारण हैं। इन दिनों वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी होती है। सामान्य जन-जीवन वर्षा के कारण थोड़ा अस्त-व्यस्त व गृहकेन्द्रित हो जाता है। यदि आध्यत्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो देवशयन कभी होता ही नहीं। जिसे निद्रा छू ना सके और जो व्यक्ति को निद्रा से जगा दे वही तो ईश्वर है।

विचार कीजिए परमात्मा यदि सो जाए तो इस सृष्टि का संचालन कैसे होगा! 'ईश्वर' निद्रा में भी जागने वाले तत्व का नाम है और उसके प्राकट्य मात्र से व्यक्ति भी निद्रा से जागने में सक्षम हो जाता है। गीता में भगवान् कृष्ण कहते हैं 'या निशा सर्वभूतानाम् तस्यां जागर्ति संयमी' अर्थात् जब सबके लिए रात्रि होती है, योगी तब भी जागता रहता है। इसका आशय यह नहीं कि शारीरिक रूप से योगी सोता नहीं; सोता है किंतु वह चैतन्य के तल पर जागा हुआ होता है।

निद्रा का नाम ही संसार है और जागरण का नाम 'ईश्वर'। आप स्वयं विचार कीजिए कि वह परम जागृत तत्व कैसे सो सकता है! देवशयन; देवजागरण ये सब व्यवस्थागत बातें हैं। वर्तमान पीढ़ी को यदि धर्म से जोड़ना है तो उन्हें इन परंपराओं के छिपे उद्देश्यों को समझाना आवश्यक है। हम देवशयन को अपनी कामनाओं व वासनाओं के संयम के संदर्भ में देखते हैं। हमारे शास्त्रों में भी देवशयन की अवधि में कुछ वस्तुओं के निषेध एवं वर्जनाओं के पालन का निर्देश है, जिससे साधक देवशयन की अवधि में संयमित जीवन-यापन कर सकें। देवशयन हमें त्याग के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक होता है।

आइए शास्त्रानुसार जानें कि देवशयन की अवधि में साधक के लिए कौन से नियम व अनुशासन का पालन करना श्रेयस्कर है-

1. जो साधक वाक-सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे देवशयन की अवधि में मीठे पदार्थों का त्याग करें।

2. जो साधक दीर्घायु व आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं वे देवशयन की अवधि में तली हुई वस्तुओं का त्याग करें।

3. जो साधक वंशवृद्धि व पुत्र-पौत्रादि की उन्नति चाहते हैं वे देवशयन की अवधि में दूध एवं दूध से बनी वस्तुओं का त्याग करें।

4. जो साधक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं वे देवशयन की अवधि में धातु के पात्र का त्याग कर पत्तों (पातल) पर भोजन करें।

5. जो साधक अपने समस्त ज्ञात-अज्ञात पापों का क्षय करना चाहते हैं वे देवशयन की अवधि में 'अयाचित' अथवा 'एकभुक्त' भोजन करें।

'अयाचित' से आशय उस भोजन से है जो याचना रहित अर्थात् बिना मांगे प्राप्त हो।

'एकभुक्त' से आशय केवल एक बार भोजन करने से है।

मंगलवार को करें नीम के पेड़ की पूजा, होंगे 5 चमत्कारिक फायदे

मंगल की दिशा दक्षिण मानी गई है। नीम का पेड़ मंगल की स्थिति तय करता है कि मंगल शुभ असर देगा या नहीं। अतः दक्षिण दिशा में नीम का एक बड़ा सा वृक्ष जरूर होना चाहिए। यदि दक्षिणमुखी मकान के सामने द्वार से दोगुनी दूरी पर स्थित नीम का हराभरा वृक्ष है या मकान से दोगना बड़ा कोई दूसरा मकान है तो दक्षिण दिशा का असर कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा। आओ जानते हैं नीम के पेड़ की पूजा करने के 5 फायदे।

1. नीम का पेड़ साक्षात मंगलदेव है। इसकी पूजा करने से मंगलदोष दूर होते हैं।

2. मंगलवार को नीम के पेड़ में शाम को जल चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार करें। इससे हनुमानजी की कृपा प्राप्त होगी। घर के

पास नीम का पेड़ लगाने और नित्य इसमें जल अर्पित करने से हनुमानजी की भी कृपा बनी रहती है।

3. इस पेड़ की सेवा करने से आपके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होगा और मंगलदोष दूर हो जाएगा।

5. नीम की पूजा करने और इसकी दातून करने से शनिदोष भी समाप्त हो जाता है।

ज्योतिष में कहीं कहीं नीम का संबंध शनि और कहीं कहीं केतु से जोड़ा गया है। इसलिए दोनों ही ग्रहों की शांति हेतु उचित दिशा में नीम का पेड़ लगाया जा सकता है। नीम की लकड़ी से हवन करने से शनि की शांति होती है। इसके पत्तों को जल में डालकर स्नान करने से केतु संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। नीम की लड़की की माला धारण करने से शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। यदि आपका जन्म उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या आपकी राशि मकर या कुंभ राशि है तो नीम का पेड़ लगाने बहुत ही शुभफलदायी होगा।

अब रिटेल इन्वेस्टर भी खुलवा सकेंगे रिजर्व बैंक में खाता, जानिए कैसे और क्यों मिल रही है यह सुविधा

नई दिल्ली। एजेंसी

अब रिटेल इन्वेस्टर सरकारी बॉन्ड्स में सीधे निवेश कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक डेडिकेटेड बॉन्ड खरीद विंडो को खोल दिया। इसका मकसद बैंकों और पूल किए गए संसाधनों जैसे म्यूचुअल फंड के प्रबंधकों से परे सरकारी डेट सिक्योरिटीज के स्वामित्व को लोकतांत्रिक बनाना है। आरबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक, योजना के शुरू होने की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। अब रिटेल इन्वेस्टर सरकारी बॉन्ड्स को आरबीआई के 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (RDG) अकाउंट' के जरिए खरीद व बेच सकेंगे। आरबीआई के मुताबिक, रिटेल इन्वेस्टर्स (व्यक्तियों) के पास अब आरबीआई के साथ RDG अकाउंट खुलवाने और मेंटेन करने की सुविधा होगी।

कैसे खुलेगा खाता

RDG अकाउंट्स को इस स्कीम के लिए उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल यानी RBI रिटेल डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खोला जा सकेगा। 'ऑनलाइन पोर्टल' रजिस्टर्ड यूजर्स को सरकारी सिक्योरिटीज (Government Securities) के प्राइमरी इश्युएंस तक पहुंच और एनडीएस-ओएम तक पहुंच भी उपलब्ध कराएगा। RDG अकाउंट को सिंगल या जॉइंट में खोल सकते हैं।

नहीं लगेगी कोई फीस

RBI RDG अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। ''अउ अकाउंट का इस्तेमाल करके एक बचतकर्ता प्राइमरी मार्केट से खरीद कर सकता है, जिस पर अभी तक बॉन्ड हाउसेज या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वर्चस्व है। हालांकि खुदरा भागीदारी से सॉवरेन बॉन्ड बाजार के परिदृश्य में भारी बदलाव नहीं आ सकता है। यह निवेश की सुरक्षा और सुनिश्चित रिटर्न की तलाश करने वाले बचतकर्ताओं के लिए एक नया निवेश विकल्प खोल सकता है।

पात्रता शर्तें

- रिटेल इन्वेस्टर का भारत में बचत खाता होना चाहिए।
- पैन होना चाहिए।
- केवाईसी के लिए कोई भी मान्य दस्तावेज होना चाहिए।
- वैलिड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- एक अनिवासी भारतीय भी पात्र है बशर्ते कि वह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अनुपालन करता हो।

क्या होगा प्रॉसीजर

रजिस्ट्रेशनः निवेशक ऑनलाइन फॉर्म भरकर ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म को प्रमाणित करने व जमा करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग कर सकते हैं। सफल रजिस्ट्रेशन पर 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट' खोला जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंचने के लिए एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से विवरण दिया जाएगा। आरडीजी खाता प्राथमिक बाजार भागीदारी के साथ-साथ एनडीएस-ओएम पर द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए उपलब्ध होगा।

प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेशन

सिक्योरिटीज की भागीदारी और आवंटन सरकारी सिक्योरिटीज की प्राथमिक नीलामी में भाग लेने के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी योजना और एसजीबी जारी करने के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। प्रति सिक्योरिटी केवल एक बोली की अनुमति है। बोली जमा करने पर देय कुल राशि प्रदर्शित की जाएगी। एग्रीगेटर/प्राप्तकर्ता कार्यालय को भुगतान नेट बैंकिंग/यूपीआई से किया जा सकता है। अगर कोई रिफंड है तो एग्रीगेटर द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार इसे निवेशक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। निवेशकों को आवंटित सिक्योरिटीज, सेटलमेंट के दिन उनके आरडीजी खाते में जमा करके जारी की जाएंगी।

रजिस्टर्ड निवेशक एनडीएस-ओएम (ऑड लॉट सेगमेंट/आरएफक्यू) के माध्यम से सरकारी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सेकंडरी बाजार लेनदेन लिंक का उपयोग कर सकते हैं।

खरीदः ट्रेडिंग घंटे शुरू होने से पहले या दिन के दौरान, निवेशक को लिंक किए गए बैंक खाते से नेट-बैंकिंग/यूपीआई का उपयोग करके सीसीआईएल (क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ एनडीएस-ओएम) के नामित खाते में पैसा ट्रान्सफर करना चाहिए। वास्तविक ट्रान्सफर/सफलता संदेश के आधार पर, 'बाई' ऑर्डर देने के लिए एक फंडिंग सीमा (खरीद सीमा) दी जाएगी। ट्रेडिंग सत्र के अंत में, निवेशक के क्रेडिट में पड़े किसी भी अतिरिक्त फंड को वापस कर दिया जाएगा।

UPI सुविधा का उपयोग करते हुए, जिसके द्वारा लिंक किए गए बैंक खाते में धनराशि को ऑर्डर देते समय ब्लॉक किया जा सकता है, सेटलमेंट के दिन पैसे को इस खाते से डेबिट किया जाएगा। इसी प्रकार की सुविधा बैंकों के माध्यम से यथासमय उपलब्ध कराई जाएगी। खरीदी गई सिक्योरिटीज को सेटलपमेंट के दिन आरडीजी खाते में जमा किया जाएगा।

बिक्रीः बिक्री के लिए पहचानी गईं सिक्योरिटीज को ट्रेड के सेटलमेंट तक ऑर्डर प्लेस करने के समय ब्लॉक कर दिया जाएगा। बिक्री लेनदेन से प्राप्त राशि को सेटलमेंट के दिन लिंक किए गए बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

निवेशकों के लिए अन्य सर्विसेज

रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाते में सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और शेष राशि की स्थिति, प्रदान किए गए लिंक से प्राप्त की जा सकती है। सभी लेनदेन अलर्ट ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

आरबीआई आरडीजी अकाउंट में नॉमिनेशन की सुविधा है। निर्धारित प्रारूप में नामांकन फॉर्म भरकर अपलोड किया जा सकता है। इसमें अधिकतम दो नॉमिनी हो सकते हैं। रजिस्टर्ड निवेशक की मृत्यु की स्थिति में, आरडीजी खाते में उपलब्ध सिक्योरिटीज को मृत्यु प्रमाण पत्र और ट्रांसमिशन फॉर्म जमा करने पर नामांकित व्यक्ति के आरडीजी खाते या किसी अन्य सरकारी सिक्योरिटी खाते में प्रेषित किया जा सकता है।

आरडीजी खाते में रखी गई सिक्योरिटीज को जरूरत पड़ने पर गिरवी रखा जा सकता है।

'रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर' के पास अन्य रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को सरकारी सिक्योरिटीज को उपहार में देने की ऑनलाइन सुविधा होगी।

'रिटेल डायरेक्ट' योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न या शिकायत पोर्टल पर डाली जा सकती है, जिसे लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) मुंबई, आरबीआई द्वारा नियंत्रित/समाधान किया जाएगा।

प्राथमिक नीलामी में बोली जमा करने के लिए एग्रीगेटर द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।भुगतान गेटवे आदि के लिए अगर कोई शुल्क लागू है तो वह रजिस्टर्ड निवेशक द्वारा वहन किया जाएगा।

डायरेक्ट एजेन्टों के चयन के लिए विज्ञप्ति जारी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत इन्दौर मौफसिल संभाग, इन्दौर के क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण इन्दौर, देवास तथा धार जिले में कार्य करने के लिए आकर्षक इंसेन्टिव कमी'शन के आधार पर भारतीय डाक विभाग की अति लोकप्रिय तथा अधिकतम रिटर्न देने वाली डाक जीवन बीमा योजना तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के व्यवसाय अर्जन के लिये डायरेक्ट एजेन्टों का चयन किया जाना हैं । चयन के लिए साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 26.07.2021 को समय 11.30 बजे किया जाना हैं । निम्न अर्हताए पूर्ण करने वाले इच्छुक उम्मीदवार स्वयं का बायोडॉटा तथा वांछित दस्तावेजों प्रमाण-पत्रों (जन्म प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र तथा अन्य कोई संबंधित प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो इत्यादि) सहित कार्यालय अधीक्षक डाकघर, इन्दौर मौफसिल संभाग, जीपीओ परिसर, इन्दौर 452001 में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित हो सकते है। । आवेदन तथा अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए निकटतम डाकघर अथवा विकास अधिकरी (पीएलआई), इन्दौर मौफसिल संभाग, इन्दौर से मोबाईल क्रमांक 7587598466 पर संपर्क कर सकते हैं ।

वांछित अर्हताए

1. शैक्षणिक योग्यता :- 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष

2. आयु सीमा :- 18 वर्ष से 50 वर्ष

3. इच्छुक उम्मीदवार को कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिये ।

4. इच्छुक उम्मीदवार को स्थानीय भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिये ।

5. मार्केटिंग और सेल्स का अनुभव रखने वाले उम्मदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी ।

सौर क्षेत्र में वित्त पोषण 193 प्रतिशत बढ़ाः रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत समेत वैश्विक सौर क्षेत्र को इस साल जनवरी-जून के दौरान कुल वित्त पोषण सालाना आधार पर लगभग तीन गुना बढ़कर 13.5 अरब डॉलर रहा। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। स्वच्छ ऊर्जा पर परामर्श देने वाली मेरकॉम कैपिटल ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यम पूंजी समेत कुल कंपनी वित्त पोषण 2020 की इसी अवधि में 4.6 अरब डॉलर था। मेरकॉम कैपिटल ग्रुप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज प्रभु के अनुसार, ''पिछले साल के मुकाबले 2021 की पहली छमाही में वित्त पोषण चौतरफा रहा। पिछले साल महामारी का काफी असर दिखा था। विलय एवं अधिग्रहण सौदे बढ़े हैं। सौर कंपनियां परियोजनाएं बढ़ा रही हैं। तेल एवं गैस कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा में जा रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं खरीदने के लिये पूंजी जुटायी जा रही है।''

ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, मिल सकता है ज्यादा ब्याज

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पीएफ अकाउंट पर ज्यादा ब्याज मिल सकता है। एक रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ईपीएफओ अपने सालाना जमा का एक हिस्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी इनविट्स (InvITs) में निवेश करने की योजना बना रहा है। इससे न केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश में तेजी आएगी बल्कि ईपीएफओ के लिए इनवेस्टमेंट का दायरा भी बढ़ेगा।

ईपीएफओ अब तक केवल बॉन्ड्स, सरकारी सिक्योरिटीज और ईटीएफ में ही निवेश करता है। इनविट एक ऑल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड (AIF) है जो म्युचुअल फंड की तरह काम करता है। यह मार्केट रेग्युलेटर सेबी के दायरे में है। एक अधिकारी ने कहा कि ''ध्इ में इनविट्स सही विकल्प है। लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्टर सेक्टर में लॉन्ग टर्म फंड्स की मांग है। यह ईपीएफओ को परंपरागत निवेश विकल्पों से इतर निवेश का विकल्प देता है।

बजट में संकेत

आम बजट में सरकार ने इंस्टीट्यूशंस से और पैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर में डालने का संकेत दिया था। माना जा रहा है कि इनविट्स के जरिए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पेंशन फंड्स से लॉन्ग टर्म फंड जुटा सकते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्स, एसएमई फंड्स और सोशल वेंचर फंड्स AIF के कैटगरी 1 सेगमेंट में कुछ विकल्प हैं और इन पर सेबी के नियम लागू होते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने ईपीएफओ को इसमें निवेश करने की अनुमति दे दी है। लेकिन इनमें इनविट्स ही सबसे तेजी से उभरता विकल्प है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि एआईएफ से हमें अपने डिपॉजिट्स के निवेश के लिए व्यापक विकल्प मिला है। लेकिन हमें केवल कैटगरी 1 और कैटगरी 2 में ही निवेश की अनुमति है। इसमें इनविट्स में ज्यादा संभावनाएं हैं। ये प्राइवेट और पीएसयू दोनों में है। अगर सेंट्रल बोर्ड केवल गवर्नमेंट सेक्टर में निवेश की अनुमति देता है तो ईपीएफओ इस विकल्प पर विचार कर सकता है। सेंट्रल पीएफ कमिश्नर सुनील बर्थवाल ने कहा कि सरकार ने हमें अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा ऑल्टरनेटिव फंड्स में निवेश करने की अनुमति दे दी है। लेकिन हम किसमें निवेश करेंगे, इसका फैसला सेंट्रल बोर्ड करेगा।

पीएफ सब्सक्राइबर्स को क्या फायदा

पीएफ अकाउंट होल्डर्स को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज मिलेगा। माना जा रहा है कि यह ब्याज अगस्त के अंत में पीएफ अकाउंट होल्डर्स के खाते में डाल दिया जाएगा। अगर ईपीएफओ अपने कॉर्पस का कुछ हिस्सा इनविट्स में निवेश करता है तो उसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो पीएफ सब्सक्राइबर्स को ज्यादा ब्याज मिल सकता है।

डब्ल्यूएचओ का दावा: कोरोना का डेल्टा स्वरूप 104 देशों में फैला

नई दिल्ली। एजेंसी

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना का नया स्वरूप डेल्टा दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इसके चलते उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को आगाह करते हुए कहा कि 104 देशों तक पहुंचने वाला डेल्टा वैरिएंट जल्द ही पूरी दुनिया में कोरोना के स्वरूपों में सबसे अधिक हावी हो सकता है। डब्लूएचओ प्रमुख टैड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने कहा कि पिछला सप्ताह ऐसा चौथा सप्ताह था, जब दुनिया भर के मामले बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहा। डब्ल्यूएचओ के छह क्षेत्रों में से एक को छोड़कर अन्य सभी में मामले बढ़े हैं।

उन्होंने कहा कि 10 सप्ताह तक संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद इस तरह मामले बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। संगठन के महानिदेशक ने कहा कि कोरोना का नया स्वरूप डेल्टा वैरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिससे संक्रमण के मामले और उससे जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। खासतौर पर ये वैरिएंट उन लोगों को संक्रमित कर रहा है, जिन्होंने टीका नहीं लिया है। इस वजह से स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं, जिन देशों में टीकाकरण की दर बेहद कम है, वहां हालात और भी खराब हैं। उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी कि डेल्टा वैरिएंट अधिक संक्रामक है, इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है।

अमेरिका : जहां नहीं लगवा रहे टीका वहां डेल्टा का कहर

कोरोना वायरस के नए रूप की चपेट में आने से बचने के लिए वैज्ञानिक कह चुके हैं कि सभी को जल्द से जल्द टीका लगवाना होगा। वैज्ञानिकों ने ये भी स्पष्ट किया है कि टीका लगवाने वाले लोगों को भी संक्रमण हो सकता है लेकिन उनकी सेहत को नुकसान होने की संभावना उन लोगों की तुलना में कम है जो बिना टीके के संक्रमित होंगे। अमेरिका में डेल्टा वैरिएंट से संक्रमित होने वालों की दर 70 से 80 फीसदी है।

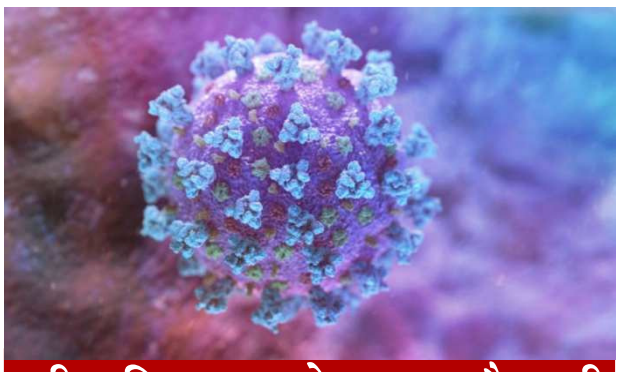

पूरी दुनिया पर हो सकता है हावी

अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन डॉ. आशीष झा का कहना है कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण के अधिक मामले उन क्षेत्रों में कम देखने को मिल रहे हैं जहां टीकाकरण की दर कम है या जहां लोग टीका लगवाने में संकोच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। ऐसे ही क्षेत्रों में संक्रमण के मामले अधिक दिख रहे हैं, खासतौर से लोग डेल्टा वैरिएंट की चपेट में आ रहे हैं।

टीका और डेल्टा का सीधा संबंध

डॉ. झा के अनुसार मैसाच्युसेट्स और रोड आईलैंड में 85 से 90 फीसदी वयस्कों को टीका लग चुका है। इसका नतीजा ये है कि इन क्षेत्रों में संक्रमण की दर कम है। वहीं अरकंसास, ओहियो समेत अन्य क्षेत्रों में टीकाकरण की दर बहुत कम है। नतीजा ये है कि यहां कोरोना का डेल्टा वैरिएंट बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि टीका और डेल्टाका सीधा संबंध है।

दोबारा संक्रमण के मामले बेहद चिंताजनक

डॉ. झा का कहना है कि दुनिया के 95 से अधिक देशों में फैल चुका है। ऑस्ट्रेलिया, इस्राइल और दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा वैरिएंट ने कहर बरपाना भी शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात ये है कि अब तक टीका न लगवाने वाले लोग इस रूप की चपेट में अधिक आ रहे हैं। दोबारा संक्रमण के मामले भी सामने आए हैं जो भविष्य के लिए चिंताजनक स्थिति है।

स्पूतनिक-वी डेल्टा समेत सभी वैरिएंट के खिलाफ असरदार

देश में इस्तेमाल हो रहे रूस का स्पूतनिक-वी टीका डेल्टा समेत कोरोना के सभी वैरिएंट के खिलाफ असरदार है। रूस के गमाल्या रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये दावा एक ताजा अध्ययन के नतीजों के आधार पर किया है। आरडीआईएफ ने बताया है कि कोरोना के नए वैरिएंट पर टीके के प्रभाव को जांचने के लिए शोध में पाया गया है कि स्पूतनिक-वी टीका सभी नए वैरिएंट अल्फा, बीटा, गामा यहां तक की डेल्टा के खिलाफ भी प्रोटेक्टिव न्यूट्रलाइजिंग तत्व तैयार करता है। मालूम हो कि स्पूतनिक-5 टीका भारत समेत दुनिया के 67 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। एजेंसी

टीका न्यूट्रलाइज करने में सक्षम...

आरडीआईएफ के सीईओ किरिल दिमित्रेव ने बताया कि स्पूतनिक-वी टीके की दो डोज कोरोना के नए वैरिएंट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि अन्य टीकों की तुलना में स्पूतनिक ज्यादा असरदार और प्रभावी है। वैज्ञानिकों ने परीक्षण में टीके की वायरस न्यूट्रलाइजिंग एक्टिविटी (वीएनए) को परखा तो पता चला कि वायरस के खिलाफ टीके का प्रभाव वैज्ञानिक भाषा में गोल्ड स्टैंडर्ड है।

एफडीसी लिमिटेड ने भारत का पहला फेविपिरावीर ओरल सस्पेंशन, फॅवेन्ज़ा लॉन्च किया

खुराक लेना आसान बनाते हुए, ओरल सस्पेंशन खुराक लेने की आवृत्ति को कम करने में मदद करता है

मुंबई। एजेंसी

घरेलू फार्मा कंपनी, एफडीसी लिमिटेड ने आज भारत के पहले फेविपिराविर-फॅवेंजा ओरल सस्पेंशन को लॉन्च करने की घोषणा की। फेविपिराविर-फॅवेंजा का उपयोग कोविड-19 के हल्के से मध्यम मामलों का इलाज करने में किया जाता है। सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन से मिलने वाला यह सस्पेंशन वर्तमान में पूरे देश के सभी खुदरा दवा दुकानों और अस्पताल के फार्मेसियों में उपलब्ध है।

फॅवेंज़ा सस्पेंशन अद्वितीय है, क्योंकि इसकासुविधाजनक लोडिंग डोज़ (पहले दिन) सुबह में 18 मिली और शाम को 18 मिली होता है, जो फेविपिराविर 400एमजी की 9 गोलियों के बराबर हैं। यह कोविड-19 के इलाज की प्रक्रिया को आसान बनाता है।

श्री मयंक टिक्खा, जनरल मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एंड कमर्शियल एक्सीलेंस, एफडीसी लिमिटेडने बताया कि 'पॉजिटिव मामलों के फिर बढ़ रहे हैं, इसलिए यह हमारे देश में हेल्थ सर्विस वॉरियर्स को इस बीमारी के खिलाफ इस निरंतर लड़ाई में व्यवहारिक विकल्प प्रदान करने का वक्त है। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए, हम अपने रोगियों को सुविधा के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रभावकारिता प्रदान करने में विश्वास करते हैं और इस तरह हमने कोविड -19 उपचार प्रक्रिया को हर तरह से परेशानी मुक्त रखने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है।' भारत मेंविश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक मामले हैं, और हर दिन लगभग 50,000 मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कोविड के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाली तीसरी लहर का भय बना हुआ है।

थोक मुद्रास्फीति जून में घटकर हुई 12.07 प्रतिशत

खाद्य पदार्थों, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति (WPI) जून में मामूली रूप से घटकर 12.07 प्रतिशत रह गई। हालांकि, डब्ल्यूपीआई जून में लगातार तीसरे महीने दोहरे अंकों में रही, जिसका मुख्य कारण पिछले साल का कम आधार है। जून 2020 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति ऋणात्मक 1.81 प्रतिशत थी।

विनिर्मित उत्पादों की महंगाई बनी रहने के बावजूद खाद्य पदार्थों और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते लगातार पांच महीनों की तेजी के बाद जून में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति में नरमी आई। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून 2021 (जून 2020 के मुकाबले) 12.07 प्रतिशत है, जो जून 2020 में ऋणात्मक 1.81 प्रतिशत थी।

बयान में कहा गया, जून 2021 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से कम आधार प्रभाव और पेट्रोल, डीजल (एचएसडी), नेफ्था, एटीएफ, फर्नेस ऑयल जैसे खनिज तेलों और मूल धातु, खाद्य उत्पाद, रासायनिक उत्पाद जैसे विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण है। समीक्षाधीन अवधि में ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति घटकर 32.83 प्रतिशत हो गई, जो मई में 37.61 प्रतिशत थी। इसी तरह खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति भी जून में घटकर 3.09 प्रतिशत रह गई, जो मई में 4.31 प्रतिशत थी। हालांकि, इस दौरान प्याज महंगा हुआ. विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति जून में 10.88 प्रतिशत रही, जो इससे पिछले महीने में 10.83 प्रतिशत थी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।